(b) and (c) The quantum of food-grains lifted in February, 1994 for PDS is higher than in the corresponding period in 1993, despite increase in the Central Issue Prices of foodgrains effected from 1-2-94. Levy sugar lifting is nearly 100%. Lifting of foodgrains through PDS is dependent on availability arid prices of rice, wheat and coarse grains in the open market.

(d) Yes, Sir. The estimated population in identified areas under RPDS Blocks (numbering 1752) is around 165 million.

(e) Information received from the State Governments and U.T. Administrations indicate that many State Governments are not making the allocations of foodgrains as per projected requirements for the RPDS areas due to various constraints. However, the per capita offtake of food-grains in RPDS areas is higher than in non-RPDS areas.

(f) As part of the RPDS scheme, State Governments/UT Administrations agreed to undertake distribution of additional commodities of mass consumption through the Fair Price Shops (FPS) according to local consumer needs and preferences. A number of States/UTs have reported distribution of iodised salt, tea, soaps and pulses through the FPSs in RPDS areas. The Advisory Council on PDS in its meetings reviews the progress in implementation of the RPDS.

(g) and (h) The entire country is covered by the Public Distribution System and the total population is eligible to PDS benefits.

P.D.S. facility only for needy people

4247. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :
SHRI DIGVUAY SINGH:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to provide facility only to needy people through public distribution system in the country;

(b) if so, whether any scheme has been formulated or whether Government have fixed criteria for the -classification of needy people; and

(c) if so, what are the details thereof stating the time by which the decision will be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINIS1RY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUD-DIN AHMED) : (a) to (c) The Advisory Council on Public Distribution System (PDS) in its meeting held in March, 1993 set up a Committee of State Ministers for formulating recommendations regarding a National Policy on PDS focussing on the need to ensure larger and more meaningful quantities of PDS commodities to the needy and deserving sections of the society. One of the recommendations made by the Committee of State Ministers is as follows :—

> "In order to ensure that larger and more meaningful quantities of food-grains reach the relatively needy and poorer sections, it is inescapable that the relatively better off sections of the population are excluded from access to the PDS in respect of foodgrains."

So far. the Government has not taken any decision on the report of the Committee of Ministers and it is not possible to give any specific time frame for taking a decision since several aspects have to be considered in consultation with State Governments.

सुपर बाजार और केंद्रीय भंडार के मध्य वस्तुओं के मूल्य और उनकी गुणवत्ता में अन्तर

4248. श्रीमती चन्द्रिका अग्निमन्थम जैम : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1991 से 31 दिसम्बर, 1993 तक की अवधि के दौरान क्रमशः सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार को वस्तुओं के मूल्यों और उनकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सुपर बाजार में वस्तुओं का विक्रय मूल्य केन्द्रीय भंडार की तुलना में कम है जबकि वहां पर बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में प्रायः कोई अन्तर नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्हें अप्रैल, 91 से 31 दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में 578 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । केन्द्रीय भंडार ने सूचित किया है कि उन्हें इस अवधि के दौरान सुपर बाजार की तुलना में ऊंचे मूल्य अथवा घटिया किस्म के बारे में ग्राहकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा बेची जाने वाली विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के बिक्री मूल्यों में प्रायः दोनों और अंतर देखा गया है । सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दो अलग-अलग सहकारी संगठन हैं, जिनके अधिप्राप्ति के स्रोत, अधिप्राप्ति के समय तथा लाभ के मार्जिन और अन्य लागतें अलग-अलग हैं । तथापि, दोनों संगठनों के खुदरा मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य से नीचे नियत किए जाते है ।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार को आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की बारीकी से मानीटरिंग करने की सलाह दी गई है ।

दिल्ली में राशन की वस्तुओं के वितरण के लिए नई योजना

4249. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशन की वस्तुओं के वितरण और उनकी उपलब्धता के संबंध में एक नई योजना तैयार की जा रही है या किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यह नई योजना वर्तमान योजना में किन-किन मामलों में अलग होगी;

(घ) इस योजना से किस प्रकार का सुधार सुनिश्चित किया जायेगा ?

(ङ) क्या इस संबंध में जनमत सहित सभी पहलुओं पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि सरकार भारतीय खाद्य निगम से चीनी के वितरण का कार्य लेकर लेवी चीनी के वितरण का कार्य तीन नामित अभिकरणों, अर्थात् दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भंडार को 50:30:20 के अनुपात में सौंपने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । ये अभिकरण लेवी चीनी सीधे मिलों से उठाएंगे और उसे उचित दर की दुकानों में वितरित करने की व्यवस्था करेंगे ।

(ग) और (घ) इस समय दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों से चीनी उठाता है और दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित उचित दर की दुकानों को उसकी आपूर्ति की व्यवस्था करता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित परिवर्तन से उचित दर की दुकानों को अच्छी किस्म की चीनी की समय से आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी ।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि प्रस्ताव के ब्यौरे को सभी संबंधितों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

Research Studies on PDS

4250. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether any Research Studies have been conducted by Government on various aspects of Public Distribution System which have been printed and made available to the general public; and

(b) what are the major findings of the Research Studies *on* the effectiveness of Public Distribution System' in Kerala ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUD-DIN AHMED) : (a) The Programme Evaluation Organisation (PEO) of the Planning Commission published an "Evaluation Report of the Essential Supplies Programme" in February, 1985. The National Sample Survey Organisation conducted a study on the "Utilisation of Public Distribution System" in the forty second round of the National Sample Survey during July, 1986 to June, 1987. These reports have been published.